



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार, 19 अक्टूबर, 2001/27 आश्विन, 1923

हिमाचल प्रदेश सरकार

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला, 23 अगस्त, 2001

संख्या एफ० टी० एस० II (बी०) 15-10/87.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) की धारा 81 के साथ पठित धारा 80 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित विनियमन बनाते हैं; अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम, लागू होता और विस्तार.—(1) इन विनियमनों का संक्षिप्त नाम सहभागी वन प्रबन्ध विनियमन, 2001 है।

(2) ये शामिलता भूमि सहित, ऐसे सरकारी वनों और ऐसी सरकारी भूमि को लागू होंगे, जिसे सोसाइटी और वन विभाग द्वारा सहभागी वन प्रबन्ध के लिए संयुक्त रूप में चयनित किया जाएगा।

(3) ये हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं--(1) इन विनियमनों में, जब तक कोई बात विषय या संबन्ध में विरुद्ध न हो,--

- (क) "अधिनियम" से, हिमाचल प्रदेश में लागू यथा संशोधित भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) अभिप्रेत है;
- (ख) "विवाद समावेश समूह" से संबद्ध ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि स्थानीय गैर-सरकारी संगठनों या स्थानीय समुदाय संगठनों के प्रतिनिधि और संबद्ध सहायक वन अरण्यपाल से मिलकर बना समूह अभिप्रेत है;
- (ग) "शामलात भूमि", "कुटुंब", "ग्राम पंचायत", "पंच", "प्रधान", "गांव" और "वार्ड" के वही अर्थ होंगे जो हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का 4) में क्रमशः उनके हैं;
- (घ) "विभाग" से हिमाचल प्रदेश का वन विभाग अभिप्रेत है;
- (ङ) "वन मण्डल अधिकारी" से, विभाग का प्रादेशिक वन मण्डल या वन्यजीव वन मण्डल का भार-साधक अधिकारी अभिप्रेत है;
- (च) "कार्यकारिणी समिति" से सोसाइटी की कार्यकारिणी अभिप्रेत है;
- (छ) "वन अधिकारी" से अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (2) के अधीन यथा परिभाषित वन अधिकारी अभिप्रेत है;
- (ज) "ग्राम सभा" से, सोसाइटी की ग्राम सभा अभिप्रेत है;
- (झ) "सरकार" से, हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;
- (ञ) "चरवाहा समूह" से, व्यक्तियों का समूह चाहे निवासी सदस्यों या प्रवासीय चरवाहों का समूह, जो अपनी जीविका की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए चयनित क्षेत्रों में चराई के साधनों पर आश्रित हैं, अभिप्रेत है;
- (ट) "सूक्ष्म योजना" से, सहभागी प्रबन्ध के लिए चयनित क्षेत्र में व्यापक वन प्रबन्ध और विकास योजना अभिप्रेत है;
- (ठ) "सहभागी वन प्रबन्ध" से, सोसाइटी तथा विभाग द्वारा संयुक्त रूप से शामलात भूमि सहित, सरकारी वन और सरकारी भूमि का प्रबन्ध करना अभिप्रेत है;
- (ड) "चयनित क्षेत्र" से, इन विनियमनों के विनियमन 3 के अधीन चयनित शामलात भूमि सहित, कोई सरकारी वन और सरकारी भूमि अभिप्रेत है;
- (ढ) "स्वयं सहायक समूह" से, व्यक्तियों का कोई संगठित समूह अभिप्रेत है जो सामूहिक रूप में पारस्परिक सहायता द्वारा संपदा आधारित क्रियाकलापों से अपने आर्थिक स्तर को बढ़ाने में समर्थ हों;
- (ण) "स्थान विशेष योजना" से, सूक्ष्म योजना का उप-संघटक, जो किसी स्थल के लिए तकनीकी रूप से समुचित योजना है, अभिप्रेत है;
- (त) "सोसाइटी" से, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) की धारा 3 के अधीन सहभागी वन प्रबन्ध के लिए रजिस्ट्रीकृत ग्राम वन विकास सोसाइटी अभिप्रेत है;

(ध) "राहत (सस्टेनेबल) वन प्रबन्ध" से, वह प्रबंध अभिप्रेत है, जो आर्थिक रूप से व्यवहार्य, पर्यावरण रूप से मीम्य और सामाजिक रूप से लाभप्रद हो तथा जो वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं को सन्तुलित करता हो, और

(द) "उपयोगिता समूह" से, व्यक्तियों का ऐसा समूह अभिप्रेत है जो अपनी जीविका आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सांझे प्राकृतिक साधन पर आश्रित है।

3. सम्बन्धी वन प्रबन्ध का उद्देश्य.—1. ग्राम पंचायत वार्ड के कम से कम पचास प्रतिशत मतदाताओं के हस्ताक्षरों द्वारा, वन मण्डल अधिकारी को किए गए आवेदन पर शान्तात भूमि सहित, किसी सरकारी वन और सरकारी भूमि को सहभागी वन प्रबन्ध के अधीन लाया जा सकता है। ऐसी परिणामित भूमि को चयनित क्षेत्र के रूप में जाना जाएगा।

2. चयनित क्षेत्र का, सतत वन प्रबन्ध हेतु सरकार के विस्तृत उद्देश्यों और योजना के अनुसार सोसाइटी और विभाग के बीच किए गए करार के निबन्धनों और शर्तों पर सोसाइटी और विभाग द्वारा संयुक्त रूप में प्रबन्ध किया जाएगा।

4. ग्राम वन विकास सोसाइटी.—1. ग्राम पंचायत वार्ड के लिए एक सोसाइटी होगी। फिर भी, जहां वार्ड संहत नहीं है और इसके उपग्रामों में सांझे वन, सांझे चरागाह भूमि, सांझे अधिकार और रियायतें नहीं हैं तो, प्रत्येक उपग्रामों के झुण्ड के लिए एक से अधिक सोसाइटियां बनाई जा सकेंगी। सोसाइटी, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) की धारा 3 के अधीन रजिस्ट्रीकृत की जाएगी।

2. ग्राम पंचायत वार्ड के सभी मतदाता, सोसाइटी के सदस्यों के रूप में अभ्यावेशित किए जाने के हक्दार होंगे।

5. सोसाइटी की कार्यकारिणी समिति का गठन.—कार्यकारिणी समिति निम्नलिखित से गठित होगी।

(क) प्रधान	ग्राम सभा द्वारा निर्वाचित किया जाएगा
(ख) उप-प्रधान	यथोपरि-
(ग) चार सदस्य	यथोपरि-
(घ) कोषाध्यक्ष	सोसाइटी के सदस्यों में से निर्वाचित सदस्यों द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।
(ङ) संयुक्त सचिव (महिला)	यथोपरि-
(च) वार्ड पंच	पदेन सदस्य
(छ) प्रधान महिला मण्डल	यथोपरि-
(ज) प्रतिनिधि स्थानीय महिला समूह	यथोपरि-
(झ) तीन सदस्य	सरकार के अन्य विभागों, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियों, उपयोगिता समूहों, स्वयं सहायक समूह और चरवाहा समूह द्वारा ग्राम स्तर पर गठित समितियों से सहयोजित किए जाएंगे।

(ञ) सदस्य सचिव

ग्राम सभा द्वारा चुना जाएगा।

परन्तु कार्यकारिणी समिति के कम से कम सात सदस्य, महिलाओं में से होंगे। संयुक्त सचिव, सदस्य सचिव की सहायता करेगा।

6. कार्यकारिणी समिति के सदस्यों की पदावधि.—कार्यकारिणी समिति के निर्वाचित सदस्य, कार्य ग्रहण करने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

7. कार्यकारिणी समिति की शक्तियाँ.—कार्यकारिणी समिति, अधिनियम के अधीन सरकार द्वारा 'वन अधिकारी' को यथा समनुदेशित शक्तियों का प्रयोग करेगी।

8. भोगाधिकार की सांज्ञेदारी.—सोसाइटी निम्नलिखित फायदों की हकदार होगी, अर्थात् :—

- (क) ऐसी प्राप्तियाँ जैसे कि गिरी हुई टहनियाँ, शाखाएँ, कांट-छांट, घास, फल, फूल, बीज, पत्ती, चारा और गैर इमारती लकड़ी, लघु वन उत्पादों का निशुल्क संग्रहण करने;
- (ख) करार की तारीख से कम से कम तीन वर्ष के लिए वन और पौधारोपण के संरक्षण के अध्वधीन, सभी मध्यावर्ती फसल के विक्रय आगमों;
- (घ) वन उत्पाद और भूमि से सम्बन्धित व्यावसायिक क्रिया कलापों का आयोजन और प्रोन्नत करने, और स्वयं सहायक समूहों की प्रोन्नति के लिए ऐसे अन्य क्रियाकलापों जिसमें महिलाओं को लघु ऋण सहित प्रत्यक्ष फायदे की व्यवस्था की जा सके। ऐसे प्रोन्नत किए गए कोई भी क्रियाकलाप वन भूमि के विधिक स्तर को प्रभावित नहीं करेगी;
- (च) इन फायदों द्वारा वन पर अभिलिखित अधिकार प्रभावित नहीं होंगे;
- (ङ) सरकार, चयनित क्षेत्र के भीतर वन उत्पादों पर कोई स्वामित्व प्रभारित नहीं करेगी;
- (च) पांच वर्ष के पश्चात्, सोसाइटी नए करार विलेख के आधार पर, पार्श्व के या समीप के क्षेत्रों को सम्मिलित करके, क्षेत्र का विस्तार कर सकेगी;
- (छ) करार की तारीख से 20 वर्ष के पश्चात् और सतत वन प्रबन्ध के सिद्धान्तों के आधार पर, चयनित क्षेत्र से शुद्ध विक्रय आगम का पचहत्तर प्रतिशत सोसाइटी के खाते में रखा जाएगा और शुद्ध विक्रय आगम का पच्चीस प्रतिशत सम्बद्ध ग्राम पंचायत को जाएगा; और
- (ज) भूमि और जल संरक्षण सहित, वन पुनरुत्पादन क्रियाकलापों पर शुद्ध विक्रय आगम का कम से कम चालीस प्रतिशत उपयोग करना।

परन्तु भोगाधिकार की सांज्ञेदारी के प्रयोजन के लिए कुटुम्ब एक इकाई होगी।

9. निधि.—निधि, सोसाइटी द्वारा इन विनियमनों के अधीन सदस्यों द्वारा अभिदाय और भोगाधिकार के विक्रय से उत्पन्न की जाएगी। सरकार ग्राम पंचायतों तथा गैर-सरकारी साधनों से प्राप्त निधियों सहित, सभी निधियाँ सूक्ष्म योजना प्रक्रिया द्वारा उपयोग की जाएगी।

10. लेखे रखना.—सोसाइटी द्वारा प्राप्त राशि, संवद्ध सोसाइटी के नाम से राष्ट्रीयकृत बैंक या अनुसूचित बैंक या सहकारी बैंक या डाकघर में जमा की जाएगी और सोसाइटी के प्रधान, कोषाध्यक्ष और सदस्य-सचिव के हस्ताक्षरों के अधीन प्रवर्तित की जाएगी।

11. अनुदान.—विभाग सोसाइटी को सहायता अनुदान नियमों के अधीन निधियों की उपलब्धता के अध्वधीन और सोसाइटी द्वारा सन्तोषप्रद कृत्य किए जाने पर सहायता अनुदान देगा।

12. विवादों का निपटारा.—सोसाइटी में भोगाधिकार की मांझेदारी के संबंध में किसी विवाद की दशा में, विभाग का संबद्ध उप-रेंजर, विवाद का समाधान करने के लिए कदम उठाएगा। विवाद का समाधान न होने की दशा में उप-रेंजर विवाद को अपनी रिपोर्ट के साथ विभाग के रेंज अधिकारी को निदिष्ट करेगा। रेंज अधिकारी पक्षों को सुनने के पश्चात् उप-रेंजर की रिपोर्ट प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर विवाद का समाधान करेगा।

13. अपील.—रेंज अधिकारी के विनिश्चय से, अपील विनिश्चय की तारीख से 30 दिन के भीतर विवाद समावेश समूह को दाखिल की जाएगी जो पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् अपील दाखिल करने की तारीख से 60 दिन के भीतर उसका विनिश्चय करेगा। विवाद समावेश समूह का विनिश्चय अंतिम होगा और पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा। विवाद समावेश समूह विनिश्चय की एक प्रति संबद्ध सोसाइटी और वन मण्डलाधिकारी को निशुल्क भेजेगा।

14. सूक्ष्म योजना तैयार करना.—1. सोसाइटी द्वारा, चयनित क्षेत्र के व्यापक वन प्रबंध और विकास के लिए सूक्ष्म योजना तैयार की जाएगी। विभाग सूक्ष्म योजना को तैयार करने में सोसाइटी की सहायता करेगा। सूक्ष्म योजना वन मण्डल अधिकारी द्वारा अनुमोदन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए क्रियान्वित रहेगी और तीन वर्ष के पश्चात् पुनरीक्षित की जा सकेगी सूक्ष्म योजना को ग्राम सभा में उपस्थित सदस्यों में से कम से कम 60 प्रतिशत बहुमत के साथ पारित किया जायेगा।

2. वन मण्डल अधिकारी सूक्ष्म योजना को पूर्णतः या अंशतः अनुमोदित कर सकेगा।

15. सरकार की शक्तियाँ.—इन विनियमनों में किसी बात के होते हुए भी, सरकार के पास सहभागी वन प्रबंध प्रक्रियाओं सूक्ष्म योजना, समन्वय, अनुश्रवण, सहायता अनुदान और कार्यान्वयन मंत्ररचना पर सोसाइटी को निदेश जारी करने की शक्ति होगी।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/-
विज्ञापक एवं सचिव।

[Authoritative English text of this department notification No. Fts-II (B) 15-10/87 dated 23-8-2001 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

FOREST DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla, the 23rd August, 2001

No. Fts. II (B) 15-10/87.—In exercise of the powers conferred by section 80 read with section 81 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. XVI of 1927), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following Regulations, namely:—

1. Short title, application and commencement.—(1) These Regulations may be called the Himachal Pradesh Participatory Forest Management Regulations, 2001.

(2) They shall apply to such Government forests and such Government land including the common land, which shall be selected jointly for participatory forest management by the Society and the Department.

(3) They shall come into force from the date of publication in Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. *Definitions.*—In these Regulations, unless these is anything repugnant in the subject or context:—

- (a) "Act" means The Indian Forest Act 1927 (Act No. 16 of 1227) as amended in its application to Himachal Pradesh;
- (b) "Conflict Resolution Group" means a group consisting of a representative of the concerned Gram Panchayat, a representative of the local non-government organisations or local community based organisations and the concerned Assistant Conservator of Forest.
- (c) "Common land", "family", "Gram Panchayat", "Panch", "Pradhan", "Village" and "Ward" shall have the meanings respectively assigned to them in the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 4 of 1994);
- (d) "Department" means the Himachal Pradesh Forest Department;
- (e) "Divisional Forest Officer" means the forest officer in-charge of a territorial or wildlife forest division of the Department;
- (f) "Executive Committee" means executive body of the Society;
- (g) "Forest Officer" means a Forest Officer as defined under sub-section (2) of section 2 of the Act;
- (h) "General House" means General House of the Society;
- (i) "Government" means Government of Himachal Pradesh;
- (j) "grazier group" means a group of persons, whether resident members or migratory graziers, who are dependent on the grazing resource in the selected area for meeting their livelihood needs;
- (k) "micro plan" means a holistic forest management and development plan of the are selected for participatory management;
- (l) "participatory forest management" means management of Government forest and Government land including common land managed jointly by the Society and by the Department;
- (m) "selected area" means any Government forest and Government land including common land selected under regulation 3 of Regulations;
- (n) "self help group" means any organized group of persons, who collectively by mutual help are able to enhance their economic status through resource based activities;
- (o) "site specific plan" means a sub component of the micro-plan which is a technically appropriate plan for the site;
- (p) "Society" means village forest development society registered under section 3 of the Societies Registration Act, 1860 (Act No. 21 of 1860) for participated forest management;
- (q) "sustainable forest management" means management which is economically viable, environmentally benign and socially beneficial, and which balances present and future needs; and

(r) "user group" means a group of persons dependent upon a common natural resource for sustaining its livelihood needs.

3. *Intent of participatory forest management.*—(1) On an application made to the Divisional Forest Officer signed by at least 50 per cent of the voters of a Gram Panchayat Ward, any Government forest and Government land including common land may be brought under participatory forest management. The land so identified shall be known as selected area.

(2) In accordance with the wider objectives and plans of Government for sustainable forest management, the selected area shall be managed jointly by the Society and the Department on the terms and conditions of an agreement to be entered between the Society and the Department.

4. *Village forest development society.*—(1) There shall be a Society for a Gram Panchayat Ward. However, where the Ward is not compact and the hamlets within it do not have common forests, common grazing lands, common rights and concessions, more than one Society may be formed for each cluster of hamlets. The Society shall be registered under section 3 of the Societies Registration Act, 1860 (Act No. 21 of 1860).

(2) All voters of a Gram Panchayat Ward shall be entitled to be enrolled as members of the Society.

5. *Constitution of Executive Committee of the Society.*—The Executive Committee shall consist of:—

(a) President	To be elected by the General House
(b) Vice-President	-do-
(c) Four Members	-do-
(d) Treasurer	To be nominated by the elected members from amongst the members of the Society.
(e) Joint Secretary (Woman)	-do-
(f) Ward Panch	Ex-officio member
(g) President Mahila Mandal	-do-
(h) Representative Local women group	-do-
(i) Three members	To be co-opted from the village level committees constituted by other departments of the Government, societies registered under the Societies Registration Act, 1860 (Act No. 21 of 1860), user groups, self help group and grazier group.
(j) Member-Secretary	To be elected by the General House :

Provided that atleast 7 members of the Executive Committee shall be from amongst the women. Joint Secretary shall assist the Member-Secretary.

6. *Term of office of members of the Executive Committee.*—Elected members of the Executive Committee shall hold office for a period of two years from the date of assumption of office.

7. *Powers of the Executive Committee.*—The Executive Committee shall exercise the powers of a "Forest Officer" as assigned by the Government under the Act.

8. *Usufruct Sharing*.—The Society shall be entitled to the following benefits, namely:—

- (a) to collect the yield such as fallen twigs, branches, loppings, grass, fruits, flowers, seeds, leaf fodder and non timber forest products free of cost.
- (b) to the sale proceeds of all intermediate harvest, subject to protection of forest and plantations for at least 3 years from the date of agreement;
- (c) to organize and promote vocational activities related to forest produce and land; and other activities such as promotion of self help groups which may provide direct benefits, including micro-lending to women. None of the activities so promoted shall affect the legal status of the forest land;
- (d) recorded rights over the forest shall not be affected by these benefits;
- (e) the Government shall charge no royalty on the forest produce within the selected area;
- (f) after 5 years, the Society may expand the area, on the basis of a fresh agreement deed, by inclusion of adjoining or nearby areas;
- (g) after 20 years from the date of agreement and, based on the principles of sustained forest management, 75 per cent of the net sale proceeds from the selected area shall be put into the account of Society and the remaining 25 per cent of the net sale proceeds shall go to the concerned Gram Panchayat; and
- (h) to utilize at least 40 per cent of the net sale proceeds on forest regeneration activities including soil and water conservation:

Provided that for the purpose of usufruct sharing, family shall be one unit.

9. *Funds*.—Funds shall be generated by the Society through contributions by members and the sale of usufructs under these regulations. All funds, including those received from the Government, Gram Panchayats and non-government sources, shall be utilized through the micro-planning process.

10. *Maintenance of accounts*.—The sum received by the society shall be deposited in the name of the concerned Society in a nationalized bank or scheduled bank or co-operative bank or post office and the account shall be operated under the signatures of the President, Treasurer and Member-Secretary of the Society.

11. *Grant-In-Aid*.—The department shall release Grant-in-Aid to the Society under the Grant-in-Aid Rules subject to the availability of funds and satisfactory performance of functions by the Society.

12. *Settlement of dispute*.—In case of any dispute in relation to usufruct sharing in the Society, the Deputy Ranger concerned of the Department, shall take steps to reconcile the dispute. In case the dispute is not resolved, the Deputy Ranger shall refer the dispute, along with his report to the Range Officer concerned of the Department. The Range Officer, after hearing the parties, shall resolve the dispute within 30 days from the date of receipt of report of the Deputy Ranger.

13. *Appeal*.—An appeal shall lie from the decision of the Range Officer to the conflict Resolution Group to be filed within 30 days from the date of decision, who shall decide the same within 60 days from the date of filing of appeal, after affording an opportunity of being heard to the parties. The decision of the conflict Resolution Group shall be final.

and binding on the parties. The Conflict Resolution Group shall send a copy of the decision to the Society and the Divisional Forest Officer concerned free of cost.

14. *Preparation of micro-plans.*—(1) A micro-plan shall be prepared for the holistic forest management and development of the selected area by the Society. The Department shall help the Society in preparation of the micro-plan. A micro-plan shall be operative for a period of five years from the date of its approval by the Divisional Forest Officer and may be revised after three years. The micro-plan shall be passed in the general house with at least 60 per cent majority of the members present.

(2) The Divisional Forest Officer may approve whole or part of the micro-plan.

15. *Power of the Government.*—Notwithstanding anything contained in these regulations, the Government shall have the powers to issue directions to the Society on participatory forest management processes, micro-planning, co-ordination, monitoring, grant-in-aid and implementation mechanisms.

By order,

Sd/-

F. C.-cum-Secretary.

